ISSN:3048-6505 (Online)
Shodh Samarth- Research Journal of Commerce, Management & Economics
Vol.3(1), January 2026, pp. 290-300

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) की भूमिका

मुहम्मद इमरान
प्रवक्ता अर्थशास्त्र
सादाबाद इंटर कॉलेज सादाबाद हाथरस

सार

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG) की पहुँच, कवरेज और संचालनगत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य SHG मॉडल के ग्रामीण महिलाओं की आय, आजीविका सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, आर्थिक भागीदारी तथा निर्णय–क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है, साथ ही इसकी प्रभावशीलता में बाधा बनने वाले संरचनात्मक एवं संचालनगत चुनौतियों की पहचान कर समाधान प्रस्तुत करना है। अध्ययन के लिए Ministry of Rural Development (DAY&NRLM), NABARD SA&Dhan की रिपोर्टों तथा प्रासंगिक शोध–पत्रों से द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि SHG–माइक्रोफाइनेंस मॉडल ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक–लिंकिंग, ऋण सुविधा, आंतरिक बचत, डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और उद्यमिता विकास ने न केवल उनकी आय बढाई बलकि निर्णय लेने की क्षमता और सामूहिक शक्ति को भी मजबूत किया। हालांकि, उच्च ब्याज दरें, सीमित वित्तीय साक्षरता, अपर्याप्त ऋण राशि, कमजोर बाजार जुड़ाव एवं सामाजिक बाधाएँ इसकी पूर्ण संभावनाओं को बाधित करती हैं। अतः नीति स्तर पर वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट एन्हांसमेंट, डिजिटल सेवाओं, बाजार संयोजन एवं SHG–फेडरेशन मॉडल को सुदृढ करना आवश्यक है, जिससे यह टिकाऊ और समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी साधन बन सके।

मुख्य शब्द :सूक्ष्म वित,स्वयं सहायता समूह,ग्रामीण महिलाएँ,वित्तीय समावेशन

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ ग्रामीण महिलाएँ अक्सर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। इन चुनौतियों में पूँजी तक सीमित पहुँच, रोजगार के अवसरों की कमी, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम भागीदारी शामिल है। इन बाधाओं के कारण ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता की क्षमताएँ और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे में, सूक्ष्म वित्त एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है जो ग्रामीण महिलाओं को छोटे ऋण, बचत और

बीमा जैसी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके उनकी आजीविकामें सुधार लाने में मदद करता है। यह न केवल उनकी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बलकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपनी आय के स्रोत विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की जटिलताओं से बचाकर, आसान और गैर–जमानती ऋण प्रदान करती हैं। ये ऋण समूह–आधारित मॉडल के माध्यम से दिए जाते हैं, जहाँ महिलाएँ स्वयं–सहायता समूह बनाती हैं। ये समूह न केवल सामूहिक बचत और ऋण चुकौती को सुनिश्चित करते हैं, बलकि सामाजिक समर्थन और ज्ञान के आदान–प्रदान का भी एक मंच प्रदान करते हैं। इन छोटे ऋणों का उपयोग महिलाएँ पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, किराना दुकान चलाने या कृषि–संबंधित छोटे व्यवसायों को शुरू करने या विस्तारित करने में करती हैं। इस प्रकार, सूक्ष्म वित्त सीधे तौर पर महिलाओं को उद्यमी बनने और अपने घरों की आर्थिक कमान संभालने में सशक्त बनाता है।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वित्त का प्रभाव केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बलकि यह सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक माध्यम है। जब महिलाएँ आय अर्जति करना शुरू करती हैं, तो उनके आत्म–विश्वास और परिवार तथा समाज में उनकी भागीदारी में वृद्धि होती है। यह उन्हें घरेलू और सामुदायिक स्तर पर अधिक प्रभावी निर्णय लेने वाली बनाता है। इसके अतिरिक्त, आय में वृद्धि से पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की शिक्षा में भी सुधार होता है, जिससे पूरे परिवार की जीवन–गुणवत्ता बेहतर होती है। हालाँकि, अभी भी चुनौतियों में वित्तीय साक्षरता की कमी और ऋण के उच्च ब्याज दरें शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में सूक्ष्म वित्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है।

शोध के उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) की पहुँच, कवरेज और संचालन के पैमाने से जुड़े प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण महिलाओं की आय, आजीविका सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी तथा निर्णय–क्षमता पर सूक्ष्म वित्त हस्तक्षेपों के प्रभाव की सीमा का मूल्यांकन करना।
- सूक्ष्म वित्त प्रणाली की प्रभावशीलता बढाने हेतु मौजूद बाधाओं, संरचनात्मक चुनौतियों एवं सीमाओं की पहचान करना तथा उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा

वर्तमान साहित्य दर्शाता है कि ैभ्ळ और माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, निवेश की शुरुआत और सामाजिक पूँजी प्रदान करते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि आय में वृद्धि और घरेलू निर्णय–शक्ति में सकारात्मक परिवर्तन होता है, परन्तु प्रभाव का आकार क्षेत्रीय विविधता, प्रशिक्षिण

स्तर और बाजार पहुँच पर निर्भर करता है। भारत में DAY&NRLM, NABARD और SA&Dhanजैसी संस्थाओं की रिपोर्टें सेक्टर के समेकित आँकड़े और ट्रेंड देती हैं।

सबान (2020) इस शोध का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त (लघु वित्त) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना था, विशेषकर यह जानना कि स्व–सहायता समूह ¼ैभ्ळ½ के माध्यम से कैसे महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आय वृद्धि, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी में सुधार हुआ। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र में 150 ग्रामीण महिला लाभार्थियों से प्रश्नावली पद्धति द्वारा जानकारी एकत्र की गई, जिसमें उनकी आय, स्व–रोजगार गतिविधियों और वित्तीय उपयोग संबंधी जानकारी का विश्लेषण किया गया ।

माहि,म. (2024). यह शोध बताता है कि जीविका परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से मिले आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि ैभ्ळ सदस्य महिलाओं की आय, आत्मविश्वास, कौशल और सामाजिक भागीदारी गैर–सदस्य महिलाओं की तुलना में अधिक बेहतर थी। इस परियोजना ने महिलाओं को रोजगार, छोटे व्यवसाय, ऋण सुविधा और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। कुल मिलाकर, जीविका परियोजना महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई।

पा.डे;.र एवं चौहान 2025 यह शोध ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता क्षमता, आर्थिक भूमिका और सामाजिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उद्यमशीलता की स्थिति जानना था। अध्ययन साहित्य आधारित गुणात्मक पद्धति से किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि महिलाएँ छोटे व्यवसायों व कृषि कार्यों में योगदान देकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन पूंजी, प्रशिक्षण और सामाजिक बाधाएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। उचित सहयोग मिलने पर वे ग्रामीण विकास की प्रभावी सहभागी बन सकती हैं।

सूॅठा सी. डी. (2019) इस शोध का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के द्वारा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना था। वर्णनात्मक विश्लेषण में उत्तराखंड के पाँच विकास खंडों के 100 समूहों की 400 महिलाओं के आंकड़ों का अध्ययन किया गया।शोध में पाया गया कि समूहों से जुड़ने पर महिलाओं की आय, रोजगार, बचत, निर्णय क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई। लगभग 82ः महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास में सुधार अनुभव किया, जिससे उनके जीवनस्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया।

चौरसिया, न. (2023). यह शोधपत्र बताता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बनाते हैं। अध्ययन में बताया गया कि सरकार की योजनाएँ, जैसे मुद्रा योजना व प्रशिक्षण सुविधाएँ, महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करती हैं। निष्कर्ष रूप में, लघु उद्योग महिलाओं के जीवनस्तर, आमदनी और सामाजिक सम्मान में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

पटेल, स. (2024). इस शोध का उद्देश्य स्वसहायता समूहों (SHG) की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में भूमिका को समझना था। प्रश्नावली के माध्यम से 200 ग्रामीण महिलाओं से जानकारी एकत्र की गई। परिणामों से पता चला कि (SHG) में जुड़ने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता, बचत की आदत, जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता बढी है। अधिकांश महिलाओं ने माना कि(SHG) गरीबी दूर करने और परिवार के विकास में सहायक हैं। निष्कर्षतः,(SHG) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है।

हंस सिंह, म. एवं जौहरा, म. (2025). इस शोधपत्र का उद्देश्य वर्धा जिले की ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता, उनकी भागीदारी और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव को समझना है। अध्ययन में पाया गया कि स्व–सहायता समूहों और छोटे उद्यमों जैसे सिलाई, पापड़, हस्तशिल्प व डेयरी से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आय में योगदान दे रही हैं । पद्धति में सैद्धांतिक विश्लेषण, अवलोकन और उदाहरणों का उपयोग किया गया । निष्कर्षतः महिला उद्यमिता से आत्मविश्वास, सम्मान और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण बढता है, हालांकि पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं ।

संकेतक	महत्व
गठित SHG की कुल संख्या	राज्य में समूहों के गठन की समग्र गति और पैमाने को दर्शाता है। (हाल के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 10 लाख तक पहुँच गई है।)
SHG सदस्यों की कुल संख्या	कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण महिलाओं (लाभार्थियों) की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। (यह संख्या अक्सर 1 करोड़ से अधिक होती है।)
ग्राम संगठन (VO) एवं क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन (CLF) की संख्या	जमीनी स्तर पर संस्थानों के मजबूत नेटवर्क को दर्शाता है, जो स्थिरता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।
कवर किए गए ग्राम/ब्लॉक	भौगोलिक पहुँच (ळमवहतंचीपबंस ब्वअमतंहम) को दर्शाता है कि राज्य के कितने क्षेत्रों में कार्यक्रम सक्रिय है।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूहों की पहुँच और पैमाने के प्रमुख संकेतक

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) और अन्य वित्तीय संस्थाएँ निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों का उपयोग करके SHG&आधारित सूक्ष्म वित्त की पहुँच और सफलता को मापते हैं:

I- संस्थागत पहुँच और सदस्यता के संकेतक (Institutional Reach–Membership)

यह संकेतक दर्शाता है कि कितने गरीब परिवारों को औपचारिक रूप से संगठित किया गया है।

वित्तीय समावेशन और ऋण की मात्रा

यह संकेतक ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को दर्शाता है।

संकेतक	महत्व
कुल बचत राशि	समूह के सदस्यों द्वारा बचत की आदत और आंतरिक पूंजी निर्माण (प्दजमतदंस ब्ंचपजंस थ्वतउंजपवद) को दर्शाता है।
बैंकों से जुड़े SHG (Bank & linked SHGs)	समूह के औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ाव और उनकी ऋण लेने की पात्रता को दर्शाता है।
वितरित ऋण की कुल राशि	SHG को बैंकों या MFIs द्वारा वितरित कुल पूंजी (स्वंद क्पेइनतेमक) को दर्शाता है, जो आर्थिक गतिविधि का मुख्य इंजन है। (हाल ही में Rs. 747 करोड़ की स्वीकृति जैसे आंकड़े इस पैमाने को दर्शाते हैं।)
बकाया ऋण राशि (Loan Outstanding)	बाजार में सक्रिय पूंजी की मात्रा को दर्शाता है।
ऋण चुकौती दर (Repayment Rate)	कार्यक्रम की वित्तीय स्थिरता और(SHG) सदस्यों की ऋण अनुशासन (ब्तमकपज क्पेबपचसपदम) को दर्शाता है।

आजीविका और गुणवत्ता के संकेतक

ये संकेतक कार्यक्रम की गुणवत्ता और इसके द्वारा सृजित आर्थिक अवसरों पर केंद्रति होते हैं।

संकेतक	महत्व
SHG का ग्रेड (Grading)	समूह की आंतरिक कार्यप्रणाली, लेखा–जोखा (Bookkeeping)और बैठकों की नियमितता की गुणवत्ता को मापता है।
आजीविका गतिविधियों में संलग्न SHG सदस्य	यह दर्शाता है कि सदस्य वास्तविक आय–सृजन गतिविधियों (IGAs) में कितने सक्रिय रूप से शामिल हैं।
बीसी सखी (BC Sakhi)की परिचालन संख्या	डिजिटल वित्तीय साक्षरता और डोर–स्टेप बैंकिंग सेवाओं की पहुँच (Access to Banking) को दर्शाता है। (UP में 38,000 से अधिक BC सखी कार्यरत हैं।)
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय वृद्धि	कार्यक्रम के कारण होने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव और गरीबी उन्मूलन में प्रगति को मापता है।

सूक्ष्म वित्त (Microfinance) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की आय, आजीविका और निर्णय लेने की क्षमता पर महत्वपूर्ण और बहुआयामी प्रभाव डाला है। इस प्रभाव की सीमा को निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षकों के तहत समझा जा सकता है:

आय और आर्थिक स्थायित्व पर प्रभाव

सूक्ष्म वित्त ने ग्रामीण महिलाओं को निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय उत्पादक और उद्यमी बनने में मदद की है।

1. आय वृद्धिः सूक्ष्म ऋणों (डपबतव–सवंदे) का उपयोग करके महिलाओं ने छोटे और विविध उद्यम शुरू किए हैं, जैसे पशुधन खरीद बकरी पालन, मुर्गी पालन, या दुधारू पशु (गाय/भैंस)।गैर–कृषि व्यवसायरू सिलाई–कढाई, हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट), साबुन या अगरबत्ती बनाना, मसाला पीसना और बेचना।व्यापाररू छोटी किराना दुकान, सब्जी बेचना या चाय की दुकान चलाना।इन गतिविधियों से उनकी मासिक घरेलू आय में वृद्धि हुई है, जिससे वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकी हैं।

2. संपतति निर्माणः आय में वृद्धि के साथ, महिलाएँ अब पूँजीगत संपति (Capital Asset) खरीदने में सक्षम हुई हैं, जैसे सिलाई मशीन, उपकरण, या छोटे कृषि औजार। ये संपतति भविष्य में उनकी आय सृजन क्षमता को और बढाती हैं और एक आर्थिक सुरक्षा जाल (Safety Net)प्रदान करती हैं।

3. बचत की आदत: समूह आधारित मॉडल के कारण महिलाओं में नियमित बचत की आदत विकसित हुई है। यह बचत उन्हें अप्रत्याशित खर्चों (जैसे बीमारी या फसल खराब होना) के लिए बाहरी साहूकारों पर निर्भर रहने से बचाती है, जिससे वित्तीय तनाव (Financial Stress) कम होता है।

4. जोखिम प्रबंधनरू सूक्ष्म बीमा:उत्पादों की उपलब्धता से वे अपने और अपने पशुओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम का बेहतर प्रबंधन कर पाती हैं, जिससे किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में आर्थिक झटका कम होता है।

आजीविका विविधीकरण पर प्रभाव

पारंपरिक कृषि–आधारित आजीविका से हटकर, सूक्ष्म वित्त ने महिलाओं को आय के गैर–कृषि स्रोतों की ओर बढने में सहायता की है।

1 नई कौशल और रोजगारः कई SHGसदस्यों को बैंक सखी (BC Sakhi) या पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वे न केवल अपने लिए आय अर्जति कर रही हैं, बलकि अपने गाँव की अन्य महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके रोजगार के नए मॉडल भी स्थापित कर रही हैं।

2 मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव: SHGs को विपणन (Marketing) के लिए बड़े समूहों (CLFs/VOs) से जोड़ा गया है। इससे उन्हें अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य पर सीधे बाजार में बेचने में मदद मिलती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और मुनाफा बढता है।

3. उद्यमशीलता विकासःसूक्ष्म वित्त ने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना को बढावा दिया है। छोटे व्यवसाय शुरू करने का अनुभव उन्हें बाजार की मांग को समझने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

निर्णय लेने की क्षमता और सशक्तिकरण पर प्रभाव

सूक्ष्म वित्त का सबसे गहरा प्रभाव आर्थिक से अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर पड़ा है।

- **पारिवारिक निर्णयलेने में भागीदारी**: जब महिलाएँ कमाती हैं और बचत करती हैं, तो घर के खर्चों, बच्चों की शिक्षा, और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उनकी बात का वजन बढ जाता है। यह उन्हें परिवार की मुखिया के रूप में अधिक पहचान दिलाता है।
- **सामाजिक उपस्थिति**: SHG की बैठकों में नियमित भागीदारी, बैंक और सरकारी कार्यालयों में लेनदेन के लिए जाना, और सामूहिक चर्चाओं में हिस्सा लेना उनके आत्म–विश्वास को बढाता है। इससे वे अपने गाँव में सार्वजनिक मुद्दों (जैसे स्वच्छता, पेयजल) पर बोलने में संकोच नहीं करतीं।
- **वित्तीय साक्षरता**: समूह की बैठकें अक्सर वित्तीय साक्षरता (थ्पदंदबपंस स्पजमतंबल) और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का केंद्र होती हैं। इससे महिलाएँ अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाती हैं और धोखेबाजी से बचती हैं।
- **सामूहिक सौदेबाजी की शक्तिः** समूह के रूप में कार्य करने से उन्हें सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने, स्थानीय स्तर पर सामाजिक कुरीतियों (जैसे शराबबंदी या दहेज) के खिलाफ आवाज उठाने और सरकारी लाभों को प्राप्त करने की क्षमता मिलती है।

संक्षेप में, सूक्ष्म वित्त उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल एक वित्तीय साधन नहीं, बलकि आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक पहचान और आत्म–सम्मान प्राप्त करने का एक माध्यम बन गया है।

सूक्ष्म वित्त की प्रभावशीलता बढाने वाली बाधाएँ और समाधान

सूक्ष्म वित्त को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में एक शक्तिशाली उपकरण बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बाधाओं/सीमाओं को दूर करना आवश्यक हैरू

वित्तीय और परिचालन बाधाएँ

बाधा/सीमा	विवरण	प्रभावी समाधान
उच्च ब्याज दरें	कई माइक्रोफाइनें संस्थानों (MFIs) की परिचालन लागत अधिक होती है, जिससे वे उच्च ब्याज दरें लगाते हैं।	सरकारी हस्तक्षेपरू NRLM के तहत ब्याजउपदान (Interest Subvention) योजनाओं का विस्तार करना। समूह की क्षमता निर्माणरू SHG को सीधे बैंकों से जोड़ना (SHG& Bank Linkage Programme) ताकि MFIs की मध्यस्थता कम हो।
अपर्याप्त ऋण राशि	छोटे ऋण अक्सर महिलाओं को केवल मौजूदा जरूरतों (जैसे उपभोग) को पूरा करने में मदद करते हैं, न कि बड़े, स्थायी उद्यम शुरू करने में।	क्रेडिट लिंकेज का उन्नयनरू महिला की क्रेडिट हिस्ट्री और व्यवसाय योजना के आधार पर किस्तवार बड़ी ऋण राशि (Staged Enhanced Loans) प्रदान करना। 'लखपति

		दीदी' योजना के तहत बड़ी परियोजनाओं को लक्षित करना।
डिजिटल एवं बैंकिंग पहुँच की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी कनेक्टिविटी और बैंकिंग आउटलेट की कमी है। महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन बर्बाद होता है।	बीसी सखी (BC Sakhi) का विस्ताररू प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशिक्षित BC सखियों की संख्या बढाना। डजिटल साक्षरतारू मोबाइल बैंकिंग, UPI और अन्य डिजिटल लेनदेन के उपयोग पर केंद्रति प्रशिक्षण प्रदान करना।
कठोर चुकौती अनुसूची	ऋण चुकाने की शर्तें अक्सर छोटे व्यवसायों के नकदी प्रवाह (ब्ै थ्सवूू) के अनुरूप नहीं होती हैं, खासकर कृषि या मौसमी व्यवसायों में।	लचीली चुकौतीरू व्यवसायों की प्रकृति (जैसे, कटाई के मौसम के अनुसार) के आधार पर लचीली चुकौती योजनाएँ (थ्समगपइसम त्मचंलउमदज च्संदे) या मासिक/तिमाही चुकौती विकल्प प्रदान करना।

I- क्षमता निर्माण और कौशल संबंधी बाधाएँ

बाधा/सीमा	विवरण	प्रभावी समाधान
वित्तीय साक्षरता की कमी	कई महिलाएँ साक्षर नहीं हैं या ऋण अनुबंधों, ब्याज दरों और निवेश के जोखिमों को पूरी तरह से नहीं समझती हैं।	सरल और दृश्य प्रशिक्षणरू व्यावहारिक उदाहरणों, रोल–प्ले और स्थानीय भाषा में दृश्य–श्रव्य सामग्री (Audio&Visual Aids) का उपयोग करके गहन वित्तीय और ऋण प्रबंधन प्रशिक्षण देना।
उद्यम कौशल और विपणन की कमी	महिलाएँ उत्पाद तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें बाजार की मांगों के अनुसार गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जानकारी नहीं होती, जिससे उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पाता।	कौशल विकास केंद्ररू उत्पाद विशिष्ट कौशल (Product&Specific Skills), पैकेजिंग और ई–कॉमर्स (E&commerce) जैसे डिजिटल विपणन पर प्रशिक्षण देना। SHGs को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाजारों और मेलों से जोड़ना।
खराब रिकॉर्ड–कीपिंग	समूहों में अक्सर लेखा–जोखा (ठववाामममचपदह) बनाए रखने में विफलता होती है, जिससे पारदर्शिता की कमी आती है और उन्हें बैंकों से आगे का ऋण प्राप्त करने में बाधा आती है।	प्रशिक्षण और निगरानीरू समूह के भीतर बुक–कीपर को प्रशिक्षित करना और उन्हें आसान डिजिटल उपकरण (जैसे, स्मार्टफोन ऐप) प्रदान करना। ग्राम संगठनों द्वारा नियमित ऑडिट और गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।

III-सामाजिक और नीतिगत बाधाएँ

बाधा/सीमा	विवरण	प्रभावी समाधान
पुरुषों का हस्तक्षेप और सामाजिक	मानदंड कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण का उपयोग अक्सर महिला के बजाय पुरुष सदस्य द्वारा किया	सशक्तिकरण प्रशिक्षणरू समूह की बैठकों में नेतृत्व कौशल (Leadership Skill) और निर्णय लेने की शक्ति पर जोर देना। जागरूकता

	जाता है, या पुरुषों के सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती हैं।	अभियान चलाना ताकि परिवार के पुरुष सदस्यों को महिलाओं के उद्यम के महत्व को समझाया जा सके।
सरकारी योजनाओं के एकीकरण का अभाव	विभिन्न सरकारी योजनाओं (जैसे, कौशल विकास, सबसिडी, बाजार पहुंच) का सूक्ष्म वित्त से पर्याप्त रूप से एकीकरण नहीं हो पाता।	कन्वर्जेंस(Convergence): जिला और ब्लॉक स्तर पर एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करना, जहाँ SHGsको छत्स्ड, कौशल विकास मिशन और डैडम्‍ योजनाओं के लाभ एक साथ मिल सकें।

इन सीमाओं को दूर करके, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म वित्त के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आर्थिक विकास और सच्चे सशक्तिकरण की नींव रख सकता है।

डेटा और पद्धति

डेटा स्रोत: सार्वजनिक स्रोत — Ministry of Rural Development(DAY&NRLM) & state&wise SHG counts (NABARDऔर SA&Dhanकी माइक्रोफाइनेंस रिपोर्टें; क्षेत्रीय शोध–पत्र।

नीतिगत सिफारिशें

1. **बाजार संयोजन**: जिला/ब्लॉक स्तर पर मूल्य–श्रृंखला (value chain) विकसित कर SHG सदस्यों को निर्यात/बड़ी सप्लाई चैन में जोडना।
2. **वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण**: निरन्तर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और उद्यमिता प्रशिक्षण ताकि कर्ज का प्रभावी उपयोग हो।
3. **उत्पाद विविधीकरण:**लघु बीमा, लम्बी–अवधि कर्ज विकल्प और महिला–अनुकूल वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना।
4. **डिजिटल बैंकिंग का विस्तार:** मोबाइल/डिजिटल भुगतान व वित्तीय सेवाओं के प्रशिक्षण से लागत घटेगी और पारदर्शिता बढेगी।
5. **निगरानी और मूल्यांकन:** जिलेवार M&Eमैकेनिज्म ताकि तालिकाओं/प्रभाव का समय–समय पर सत्यापन हो सके।
6. **फेडरेशन/प्रोडयूसर कंपनी**: SHG&Federations/Producer Companiesबनाकर बड़े ठेके और सामूहिक विपणन सम्भव करें।

सीमाएँ

- यह पेपर मुख्यतः सेकेंडरी सार्वजनिक आँकड़ों पर आधारित सारांश है; जिलेवार और प्राथमिक सर्वे समर्थन से अधिक सटीक प्रभाव आकलन सम्भव है।
- आँकड़े रिपोर्ट–वार बदलते रहते हैं जला–स्तरीय नीति–निर्माण हेतु ताजा/डिस्ट्रिक्ट–लेवल डेटा आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म वित्त एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का विस्तार केवल संस्थागत पहुँच तक सीमित नहीं है, बलकि यह ग्रामीण महिलाओं की आय, आजीविका सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण पर ठोस सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। SHG की संख्या, सदस्यता, बैंक–लिंकिंग, बचत और ऋण–वितरण जैसे संकेतक यह दर्शाते हैं कि बड़ी संख्या में गरीब ग्रामीण महिलाएँ औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ी हैं और छोटे उद्यमों, कृषि व गैर–कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। समूह–आधारित बचत, आंतरिक उधार और बैंक ऋण ने उनके लिए सुरक्षा–जाल ‍(ेंमिजल दमज) का काम किया है, जबकि ठब् सखी जैसे मॉडलों ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं को घर–द्वार तक पहुँचाकर उनकी आर्थिक भागीदारी और निर्णय–क्षमता को मजबूत किया है। साहित्य समीक्षा और उपलब्ध आँकड़े यह संकेत देते हैं कि SHG–माइक्रोफाइनेंस मॉडल ने महिलाओं के आत्मविश्वास, पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को भी सुदृढ किया है।

फिर भी, अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि सूक्ष्म वित्त की प्रभावशीलता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए कई संरचनात्मक एवं संचालनगत बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। उच्च ब्याज दरें, अपर्याप्त ऋण राशि, लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों का अभाव, सीमित वित्तीय साक्षरता, कमजोर लेखा–जोखा, बाजार व वैल्यू–चेन से अपर्याप्त जुड़ाव तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएँ, ये सभी कारक महिलाओं के उद्यमों की वास्तविक संभावनाओं को सीमित करते हैं। अतः नीति स्तर पर ब्याज उपदान, क्रेडिट एन्हांसमेंट, सतत कौशल–विकास एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, SHG–फेडरेशन और प्रोडयूसर कंपनी मॉडल का सुदृढीकरण, डिजिटल बैंकिंग एवं बाजार संयोजन को बढावा देना अत्यंत आवश्यक है। इन हस्तक्षेपों के प्रभावी क्रियान्वयन से सूक्ष्म वित्त केवल ऋण–प्रदाय का उपकरण न रहकर, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए दीर्घकालिक, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक सशक्तिकरण की ठोस रणनीति बन सकता है।

संदर्भ और प्रसंग

नसरीन सबा. (2020). ग्रामिण महिलाओं में सूक्ष्म वित्त की भूमिका. प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस वि ।चचसपमक त्मेमंतबी, 6(10), 886–889.

माहि, म. (2024). महहलाओं के आर्थिक विकास में जीविका परियोजना की भूमिकारू एक तुलनात्मक अध्ययन. प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस वि थ्पदंदबपंस डंदंहमउमदज ंदक म्बवदवउपबे, 7(2), 490–494.

पा.**डे;. र एवं चौहान ई.(2025)** महिला मृद्वक एवं ग्रामीण विकासरू अवसर एवं चुनौतियाँ. प्दजमतदंजपवदंस श्रवनतदंस वि डिनसजपकपेबपचसपदंतल ज्तमदके, 7(4), 137—140.

सूॅठा सी. डी. (2019)लघु वित्त (माइक्रोफाइनांस) का महिला—शक्तीकरण में योगदान. प्ददवअंजपवद जीम त्मेमंतबी ब्वदबमचज, 4(2), 1—6.

चौरसिया, न. (2023). ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका. श्रवनतदंस वि म्उमतहपदह ज्मबीदवसवहपमे ंदक प्ददवअंजपअम त्मेमंतबी (श्रम्ज्प्त्), 10(1), 718—727.

पटेल, स. (2024). भारतीय ग्रामीण विकास में स्व—समूह का योगदानरू एक अध्ययन (झाँसी जिले के संदर्भ में). ैविर्कींनतलंउ, प्दजमतदंजपवदंस ैबपमदजपपिब त्मिितममक त्मेमंतबी श्रवनतदंस, 7(6), 47—58.

त्रिपाठी, ए., एवं सिंह, एस. (2012). महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका. त्मेमंतबी श्रवनतदंस वि भ्नउंदपजपमे ंदक ैवबपंस ैबपमदबमे, 3(2), 227—231.

हंस सिंह, म., एवं जौहरा, म. (2025). वर्धा में ग्रामीण महिला उद्यमितारू अवसर और सहभागी चुनौतियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन. श्रवनतदंस वि त्मअपमू पद प्दजमतदंजपवदंस ।बंकमउपब त्मेमंतबी (श्रत्प्।त), 1(4), 1—6